भारत का नं. 1 संस्थान
कौटिल्य एकेडमी
सफलता का प्रवेश द्वार ...

Model Answer Key

Date : 16/02/2020

A- प्रारूप सतिति के सदस्य

– अध्यक्ष– भीमराव अम्बेडकर

– सदस्य– के मुन्सी

– एन गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्णा स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव (बी एल मित्र के स्थान पर)

– टी. टी. कृष्णमचारी (डी पी. खेतान के स्थान पर) के साथा

B- विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया

– ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता पर आधारित विधि के औचित्य की नहीं वरन् संसदीय प्रक्रिया की समीक्षा करने का अधिकार है।

C- चौथी अनुसूची

– राज्य सभा में सीटों का आवांटन चौथी अनुसूची में दिया गया है।

D- 124वां संविधान संशोधन अधिनियम

– आर्टिकल 15, 16, 46 से संबंधित सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की उन्नति हेतु 10 प्रतिशत आरक्षण 12 जनवरी 2019 से लागू 103 वां संसोधन है।

E- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ?

– 9 सितम्बर 1988

A. Who were the members of the Drafting Committee?

- Alladi Krishnaswami Ayyar
- N. Gopalaswami
- B.R. Ambedkar
- K.M Munshi
- Mohammad Saadulla
- B.L. Mitter
- D.P. Khaitan

B. Procedure established by Law

- It means that a law that is duly enacted by legislature or the concerned body is valid if it has followed the correct procedure. Following this doctrine means that, a person can be deprived of his life or personal liberty according to the procedure established by law.

C. Fourth Schedule

- Articles 4(1) and 80(2)

Allocation of seats in the Council of States

For each State or Union territory specified in the first column of the following table, there shall be allotted the number of seats specified in the second column thereof opposite to that State or that Union territory, as the case may be.

D. 124th Constitutional Amendment Act 2019

- Lok Sabha passed the Constitution (124th Amendment) Bill 2019 to provide 10 per cent reservation in jobs and educational institutions to economically backward section in the general category.

E. Prevention of Corruption Act was passed in which year?

- 1988

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone

F- भारत के संविधान का अनुच्छेद– 324

– भारतीय संविधान अनुच्छेद 324– निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना।

G- शून्य काल

– प्रश्नकाल के बाद समान्यतः 11 से 12 इसका समय परिवर्तित भी हो सकता है। इसमे लोक महत्व के मुद्दों पर संबंधित मंत्री से प्रश्न किये जाते हैं। आम तौर पर 1 घंटे का समय होता है। यह भारतीय संसदीय व्यवस्था की खोज।

H- रिट के प्रकारउासी

– अनुच्छेद 32 एवं 226 के तहत् 5 प्रकार की रिट होती है।

1. बंदी प्रत्यक्षीकरण
2. परमादेश
3. प्रतिषेद
4. उत्प्रेषण
5. अधिकार पृच्छा

I- एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित हैं?

– मनीला

J- सरदार स्वर्ण सिंह समिति

– सरदार स्वर्ण सिहं समिति के गठन मूल कर्तव्यों के लिए किया गया इनकी सिफारिशों के आधार पर 42 वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 क में शामिल किया गया।

K- न्यायिक सक्रियता क्या होता हैं?

– यह लोकहित विधि के शासक एवं संविधान की मूल भावना के संरक्षण का एक असमान्य अपरम्परागत किन्तु प्रभावी सकारात्मक यंत्र हे।

L- अनुच्छेद 371–सी किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान बनाता हैं?

– इस अनुच्छेद का संबंध मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों से संबंधित विशेष प्रावधानों का वर्णन है।

F. Article 324 of Indian Constitution

- Article 324 in the Indian Constitution gives power to the Election Commission to direct, control, and conduct elections to all Parliament, to the Legislature of every state and of elections to the offices of the President and Vice President held under the Constitution.

G. Zero Hour

- The time immediately following the Question Hour has come to be known as "Zero Hour". It starts at around 12 noon (hence the name) and members can, with prior notice to the Speaker, raise issues of utmost importance during this time.

H. Type of Writs

- There are five types of writs :
- Habeas Corpus
- Mandamus
- Prohibition
- Certiorari
- Quo-Warranto

I. Where is the headquarter of ASIAN DEVELOPMENT BANK located?

- Mandaluyong, Manila Philippines

J. Sardar Swarn Singh Committee

- In 1976, the Congress Party set up the Sardar Swaran Singh Committee to make recommendations about fundamental duties, the need and necessity of which was felt during the operation of the internal emergency (1975-1977). The committee recommended the inclusion of a separate chapter on fundamental duties in the Constitution.

K. What is Judicial Activism?

- Judicial activism, an approach to the exercise of judicial review, or a description of a particular judicial decision.

L. Article 371-C makes special provisions for which state?

- Manipur

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone
KAUTILYA ACADEMY INDORE

M- भाषायी अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकारी को कौन नियुक्त करता हैं?

– इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सातवीं संविधान संसोधन द्वारा 350 बी में भाषायीं अल्पसंख्याक वर्गों के विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है।

N- प्रत्यायानुदान

– जब कि सेवा या मद के लिए आकास्मिक रूप से धन की अत्यधिक एवं तुरन्त आवश्यकता हो तो इस प्रकार की मांग रखी जाती है। लोकसभा द्वारा सरकार को दिया गया एक प्रकार ब्लेंक चैक है।

O- भारत की आकस्मिकता निधी

– अनुच्छेद 267– 1950 में संसद द्वारा गठिन निधि राष्ट्रपति के अधिकार में वित्त सचिव की देख रेख में होती है।, अप्रत्याशित व्यय के लिए अग्रिम दी जाती है। जिसे बाद में संसद द्वारा प्राधिकृत कराया जा सकता है।

M. Who appoints the Special Officer for Linguistic minority and under which Article?

- Article 350B of the Constitution provides for the appointment by the President of a Special Officer for Linguistic Minorities.

N. Vote of Credit

- It is granted for meeting an unexpected demand upon the resources of India, due to the magnitude or the indefinite character of the service, the demand cannot be stated with the details ordinarily given in a budget. Hence, it is like a blank cheque given to the Executive by the Lok Sabha.

O. Contingency Fund Of India

- Article 267
- Contingency Fund is created as an emergency account to meet some urgent or unforeseen expenditure of the government.

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone
KAUTILYA ACADEMY
INDORE

PART- A 6 Marks

A- प्रस्तावना में 'पंथनिरपेक्ष' शब्द का अर्थ समझाइये।

पंथ निरपेक्षः पंथ निरपेक्ष शब्द भी भारतीय संविधान में 42 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। वस्तुतः, भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता की अवधारणा पहले से ही निहित थी। यह संविधान के भाग–3 में मौलिक अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार (अनुच्छेद 25 से 28) प्रदान किए जाने से स्पष्ट है। इसमें धर्म की स्वतंत्रता के अतिरिक्त धार्मिक कार्यों के प्रचार तथा धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता भी प्रदान की गई है।

पंथ निरपेक्षता का अर्थ है कि भारत सरकार धर्म के मामले में तटस्थ रहेगी। उसका अपना कोई धार्मिक पंथ नहीं होगा तथा देश में सभी नागरिकों को अपनी इच्छा के अनुसार धार्मिक उपासना का अधिकार होगा। भारत सरकार न तो किसी धार्मिक पंथ का पक्ष लेगी और न ही किसी धार्मिक पंथ का विरोध करेगी। भारत का संविधान किसी धर्म विशेष से जुड़ा हुआ नहीं है। पंथ निरपेक्ष राज्य धर्म के आधार पर भेदभाव न कर प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक नागरिक के रूप में व्यवहार करता है।

किसी भी कल्याणकारी राज्य से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह धार्मिक मामलों में पूर्ण तटस्थ रहेगा। अतः पंथ निरपेक्षता को 'सर्वधर्म सम्भाव' के रूप में देखा जाता है जहां राज्य की नजर में सभी पंथ बराबर होंगे। पंथ निरपेक्षता का अर्थ अधार्मिक या धर्म विरोधी होना नहीं, बल्कि सभी पंथो को समान स्वतंत्रता प्रदान करना है। उच्चतम न्यायालय ने पंथ निरपेक्षता को संविधान की बुनियादी विशेषता बतलाया है।

A. Define the term "SECULAR" used in the Preamble?

- The word 'Secular' was incorporated in the Preamble by the 42nd Constitutional Amendment in 1976. The term secular in the Constitution of India means that all the religions in India get equal respect, protection and support from the state. Articles 25 to 28 in Part III of the Constitution guarantee Freedom of Religion as a Fundamental Right.

B- राज्यों की पुर्नगठन संबंधी संसद की शक्ति का वर्णन कीजिए।

अनुच्छेद 3 के अनुसार, नये राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों की सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित कोई विधेयक संसद में राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पेश किया जाएगा। राष्ट्रपति इस विधेयक को प्रभावित राज्य के विधान मंडल को एक निश्चित समय सीमा के भीतर राय के लिए प्रेषित करेगा। पर राष्ट्रपति या संसद विधान मंडल की राय मानने को बाध्य नहीं है। इस प्रकार संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा (अनुच्छेद 4)। तात्पर्य यह कि इस प्रकार का

B. Write a short note on "Parliaments power reorganize the states".

- Article 3 assigns to Parliament the power to enact legislation for the formation of new States. Parliament may create new States in a number of ways, namely by (i) separating territory from any State, (ii) uniting two or more States, (iii) uniting parts of States and (iv) uniting any territory to a part of any State. Parliament's power under Article 3 extends to increasing or diminishing the area of any State and altering the boundaries or name of any State.
- A bill calling for formation of new States may be introduced in either House of Parliament only

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone

विधेयक, अन्य विधेयकों की तरह साधारण बहुमत से पारित किया जा सकेगा।

अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को नये राज्यों की स्थापना तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन की जो शक्ति प्राप्त है, उसे निम्नलिखित प्रकार से क्रियान्वित किया जा सकता है–

(i) वर्तमान राज्य से उसके प्रदेशों को अलग कर, या

(ii) दो या अधिक राज्यों को मिलाकर, या

(iii) दो या अधिक राज्यों के भागों को मिलाकर, या

(iv) किसी प्रदेश को किसी राज्य के साथ मिलाकर।

ज्ञात हो कि अनुच्छेद 3 में प्रयुक्त राज्य शब्द के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र भी शामिल हैं। वर्तमान में, भारत में 28 राज्य और 7 संघ शासित प्रदेश हैं।

राज्य क्षेत्रों का प्रत्यावर्तन– संसद को भारत के राज्य क्षेत्रों की सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन तथा नये राज्य क्षेत्र के निर्माण की शक्ति प्राप्त है।

C- विधि के शासन पर संक्षिप्त टिप्पणी।

हम विधि के शासन से शासित होते हैं। न्यायालय द्वारा किसी भी प्रशासनिक कृत्य का न्यायिक पुनरीक्षण किया जा सकता है। संसद द्वारा पारित संविधान का उल्लंघन करने वाले किसी कानून को न्यायपालिका द्वारा अवैध और अमान्य घोषित किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। इस तरह, न्यायालय को संविधान का रक्षक कहा जाता है।

D - भारत के संविधान की संशोधन प्रक्रिया की आलोचना क्यों की जाती हैं?

संविधान संशोधन की प्रक्रिया की आलोचना निम्न आधारों पर की जाती है।

– संसद को व्यापक शक्ति है। इस हेतु कोइ विशेषज्ञ निकाय नहीं है।

– संसद ही इसकी पहल कर सकती है। राज्य नहीं।

– अधिकांश संशोधनों पर संसद को ही शक्ति दी गई है। जबकि केवल राज्यों में केवल आधे राज्यों का समर्थन ही आवश्यक है। जबकि अमेरिका में 3/4 राज्यों की सहमति आवश्यक होती है।

– संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है।

on the recommendation of the President. Secondly, such a bill must be referred by the President to the concerned State Legislature for expressing its views to Parliament if it contains provisions which affect the areas, boundaries or name of that State.

C. Write a short note on "Rule of Law".

- Rule of law, the mechanism, process, institution, practice, or norm that supports the equality of all citizens before the law, secures a non-arbitrary form of government, and more generally prevents the arbitrary use of power. Arbitrariness is typical of various forms of despotism, absolutism, authoritarianism, and totalitarianism. Despotic governments include even highly institutionalized forms of rule in which the entity at the apex of the power structure (such as a king, a junta, or a party committee) is capable of acting without the constraint of law when it wishes to do so.

D. Why the amendment procedure of the Indian Constitution has been criticized?

The critics have criticised the amendment procedure of the Constitution on the following grounds:

1. There is no provision for a special body like Constitutional Convention (as in USA) or Constitutional Assembly for amending the Constitution. The constituent power is vested in the Parliament and only in few cases, in the state legislatures.
2. The power to initiate an amendment to the Constitution lies with the Parliament.

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone

– राज विधानमंडल द्वारा पारित किये जाने की कोई समय सीमा नहीं है।

3. Major part of the Constitution can be amended by the Parliament alone either by a special majority or by a simple majority. Only in few cases, the consent of the state legislatures is required.
4. The Constitution does not prescribe the time frame within which the state legislatures should ratify or reject an amendment submitted to them. Also, it is silent on the issue whether the states can with-draw their approval after according the same.
5. There is no provision for holding a joint sitting of both the Houses of Parliament if there is a deadlock over the passage of a constitutional amendment bill.
6. The process of amendment is similar to that of a legislative process. Except for the special majority, the constitutional amendment bills are to be passed by the Parliament in the same way as ordinary bills.

E- राष्ट्रपति शासन व्यवस्था की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए।

हमारा संविधान राष्ट्रपति के पद का सृजन करता है किन्तु शासन की प्रणाली राष्ट्रपतीय नहीं है।

शासन की राष्ट्रपतीय और संसदीय प्रणाली को समझना चाहिए और उनमें क्या भेद हैं यह ध्यान में रखना चाहिए। राष्ट्रपति प्रणाली के मुख्य लक्षण इस प्रकार हैं,

1. राष्ट्रपति राज्य का अध्यक्ष होता है और साथ ही शासनाध्यक्ष का भी। वह राज्य व्यवस्था में शीर्षस्थ होता है और राष्ट्र के जीवन में भी। वह वास्तव में कार्यपालक होता है नाममात्र का नहीं। उसमें जो शक्तियां निहित हैं उनका वह व्यवहार में और वास्तव में उपयोग करता है।
2. सभी कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मंत्रिमंडल उसे केवल सलाह देता है। यह आवश्यक नहीं है कि वह उनकी सलाह माने। वह उनकी सलाह लेकर अपने विवेक के अनुसार कार्य कर सकता है।
3. राष्ट्रपति जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। राष्ट्रपति के पद की अवधि विधान–मंडल की इच्छा पर आश्रित नहीं है। विधान–मंडल न तो राष्ट्रपति का निर्वाचन करता है और न उसे उसके पद से हटा सकता है।
4. राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के सदस्य, विधान–मंडल के सदस्य नहीं होते। राष्ट्रपति की अवधि को अवसान के

E. Highlight some of the features of the Presidential form of the Government?

- The presidential form of government is that in which the executive is not responsible to the legislature. An example of such a system of Government is the United States of America (U.S.A)

- **Essential features**

1. The president is the real executive. There is no nominal or ceremonial executive. All the powers are vested in the hands of the president.
2. The powers of the three organs namely, legislature, executive and judiciary are separated and vested in different persons.
3. Though the three organs of the government are kept apart, they are also connected by the system of checks and balances. Each organ of government exercises checks on the other two organs so that a sort of balance is established.
4. The tenure of the president is fixed. The tenure of office cannot be lessened or increased under any circumstances. President can be removed by the legislature only by a process of impeachment.

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone

पूर्व उसका विघटन नहीं कर सकता। विधान–मंडल राष्ट्रपति की अवधि को महाभियोग द्वारा ही समाप्त कर सकता है अन्यथा नहीं। इस प्रकार राष्ट्रपति और विधान–मंडल नियत अवधि के लिए निर्वाचन होते हैं और एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। एक का दूसरे में हस्तक्षेप नहीं होता।

F - नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में वर्णित सामाजिक निरयोग्यता पर टिप्पणी कीजिए।

नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के धारा 4 (i) से धारा 4 (xi) में सामाजिक निर्योग्यताओं का वर्णन है। जिसके अनुसार किसी दुकान, लोक उपहार केन्द्र, होटल या लोक मनोरंजन स्थान में उपयोग करना ; अथवा। किसी लोक उपहार गृह, होटल, धर्मशाला सराय या मुसाफिरखाने में जनसाधारण या उसके किसी विभाग के व्यक्तियों के जिसका वह व्यक्ति हो, उपयोग के लिए रखे गए किन्ही बर्तनों और अन्य वस्तुओं का उपयोग करना; अथवा निम्न बिन्दुओं को सामाजिक निर्योग्यताओं में रखा गया है।

1. नदि जल धारा, कुआ, तालाब के जल को उपयोग न करने देना।
2. जाति धर्म किसी जगह प्रवेश करने से रोकना, सवारी करने से रोकना।
3. धर्मशाल, सराय, मुसाफिरखाना में प्रवेश से रोकना।
4. जुलूस निकालने से रोकना, अभूषण के उपयोग से रोकना आदि।

ऐसे करने वाले को कम से कम एक मास ओर अधिक से अधिक छह मास की अवधि की कारावास से और ऐसे जुर्माने से भी जो कम से कम सौ रुपये और अध ाक से अधिक पाँच सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

G - भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए।

उद्देश्यों के निम्न बिन्दुओं के आधार पर लिखा जाता है।

– भ्रष्टाचार को परिभाषित करना।
– भ्रष्टाचार के दुष्प्रेरण को रोकना।
– भ्रष्टाचार रोकने वाली संस्थाओं को सशक्त करना।
– भ्रष्टाचार रोकने वाली संस्थाओं के बीच समन्वयन स्थापित करना।
– लोक सेबको पर भ्रष्टाचार से संबंधित मामला चलाने

F. Write a short note on the social disabilities mentioned in the Protection of Civil Rights Act, 1955.

Section 4 in the Protection Of Civil Rights Act, 1955

Punishment for enforcing social disabilities. Whoever on the ground of" untouchability" enforces against any person any disability with regard to-

(i) access to any shop, public restaurant, hotel or place of public entertainment; or

(ii) the use of any utensils, and other articles kept in any public restaurant, hotel, dharmshala, sarai or musafirkhana for the use of the general public or of 4 any section thereof or

(iii) the practice of any profession or the carrying on of any occupation, trade or business 5 or employment in any job or

(iv) the use of, or access to, any river, stream, spring, well, tank, cistern, water- tap or other watering place, or any bathing ghat, burial or cremation ground, any sanitary convenience, any road, or passage, or any other place of public resort which other members of the public, or 4 [any section thereof], have a right to use or have access to; or

(v) the use of, or access to, any place used for a charitable or a public purpose maintained wholly or partly out of State funds or dedicated to the use of the general public, or 4 any section thereof] etc.

G. What are the objectives of the Prevention of Corruption Act, 1988?

The Prevention of Corruption Act came into force in September 1988. It consolidated the provisions of the Prevention of Corruption Act, 1947, some sections of the Indian Penal Code, the Criminal Procedure Code, and the Criminal Law Act, 1952. The sole idea was to bring all relevant provisions in a single Act.

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone

के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना करना।

– अभियुक्त को भी अपनी बात रखने का अधिकार देना। आदि।

- The Bill is intended to make the existing anti-corruption laws more effective by widening their coverage and by strengthening the provisions.
- The 1988 Act enlarged the scope of the term 'public servant' and in-cluded a large number of employees within its ambit
- If the offence against the public servant is proved in the courts, it is punishable with imprisonment of not less than six months but extending to a maximum period of five years.

H - एन.जी.ओ क्या हैं? इन्हें किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता हैं?

कोफी अन्नान कहते हैं। इसकी 21 वीं शताब्दी एन. जी. ओ. की शताब्दी होगी।

एन. जी. ओ. एक ऐसा निजी संगठन है। जो लोगों के दुखः दर्द दूर करने, गरीबों के हितों का संवर्धन करने पर्यावरण रक्षा एवं बुनियादी सामाजिक सेवा देता है। जो वैधानिक रूप से गठित होता है। लेकिन सरकार से स्वतंत्र होकर कार्य करता है। इन्हें निम्न प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।

– वित्त
– पैशेवर कर्मचारी
– नौकरशाहों का रवैया
– अपर्याप्त सूचना।
– जनसहयोग की कमी।
– राजनीतिक हस्तक्षेप
– भागीदार की बजाय लाभार्थी बनने की आकांक्षा।
– जातिवाद, सम्प्रदायवाद, भ्रष्टाचार, अविश्वास की भावना आदि।

H. What is N.G.O? Throw light on the problems faced by them.

A non-governmental organization (NGO) is a non-profit, citizen-based group that functions independently of government. NGOs, sometimes called civil societies, are organized on community, national and international levels to serve specific social or political purposes, and are cooperative, rather than commercial, in nature.

Examples of NGOs include those that support human rights, advocate for improved health or encourage political participation.

NGOs are focused on giving aid and support for further development, regardless of the themes set out. However, NGOs at current face several problems to which they are not always prepared for.

1. Lack of Funds
2. No Strategic Planning
3. Absence of networking
4. Lack of maintenance

I- भारत का संविधान सी ए जी की स्वतंत्रता को कैसे सुनिश्चित करते हैं?

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148–151 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का विशद विवेचन किया गया है। यह भारत की संपरीक्षा और लेखा प्रणालियों का निष्पक्ष प्रधान होता है। इसकी निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए संविधान में निम्नलिखित प्रावधान किये गये हैं–

(i) इसे संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर साबित कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर ही हटाया जा सकेगा,

I. How does the Indian constitution ensure the independence of the CAG?

- The CAG is an authority established by the constitution of India and is independent from govt's influence. It has been formed to keep a check on govt's revenues and expenditures.
- The CAG is appointed by the President and can only be removed from office in like manner and on like grounds as a judge of the Supreme Court. The salary & other conditions of service are determined by Parliament and cannot be changed to his disadvantage post-appointment.

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone
KAUTILYA ACADEMY INDORE

(ii) इसकी सेवा–शर्तों का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है।

– सेवा मुक्त होने के बाद वह भारत सरकार के अधीन काई लाभ का पद नहीं धारण करेगा,

– उसका वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाएगा।

– उसके वेतन व भत्तों को आर्थिक आपातकाल की स्थिति के अतिरिक्त सेवाकाल के दौरान अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।

– नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के समस्त वेतन, भत्ते, पेंशन आदि भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं।

– वह भारत तथा प्रत्येक राज्य और प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्र की संचित निधि से किये जाने वाले सभी व्यय की संपरीक्षा करेगा तथा इस सम्बन्ध में यह प्रतिवेदन देगा कि क्या कोई ऐसा व्यय विधि के अनुसार नहीं किया गया है।

- The administrative expenses upon the Consolidated Fund of India.

J - भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की क्या जिम्मेदारियों हैं?

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम 2002 के अधीन किया गया था। इसके निम्नलिखित जिम्मेदारी हैं।

– प्रतिस्पर्द्धा पर हानिप्रद प्रभाव डालने वाले कार्य व्यवहारों को रोकना।

– बाजारों में प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देना और उसे बनाये रखना।

– उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना।

– व्यापार की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना।

प्रतिस्पर्द्धा (संसोधन) अधिनियम 2007 द्वारा प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम 2002 में कुछ बदलाव शामिल किये गये हैं जिनमें सीसीआई के आदेशों के मामले में अपीलों की सुनवाई के लिए एक प्रतिस्पर्द्धा अपीलीय अधिकरण (सीएटी) का गठन शामिल है।

J. What are the responsibilities of the Competition Commission of India?

1. To eliminate practices having adverse effect on competition, promote and sustain competition, protect interests of consumers and ensure freedom of trade by other participants
2. Inquire into certain agreements and dominant position of enterprise.
3. Inquiry into combinations– Section 20 of the Act entrusts the Commission with the power to inquire into any information relating to acquisition and determine whether such combination or acquisition may have an appreciable adverse effect on competition (AAEC).
4. Reference of an issue by a statutory authority to the Commission– Section 21 of the Act enumerates that in the course of a proceeding if any issue is raised that any decision of a statutory authority will be in conflict with the provisions of the Competition Act, 2002, the statutory authority shall make a reference in this regard to the Commission.
5. Reference by Commission– Section 21A of the Act provides that if in the course of proceeding an issue is raised by any party that any decision taken by the Commission is in contravention of the provisions of Competition Act, whose authority is entrusted to a statutory authority then the Commission may make a reference in respect of the issue to the statutory authority.

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone

5. Power to issue interim order– Section 33 of the Act empowers the Commission to issue interim orders in cases of anti-competitive agreements and abuse of dominant position, thereby temporarily restraining any party from carrying on such an act.
6. Competition Advocacy– Section 49 of the Act provides for competition advocacy and enumerates that the Central or the State Government may while formulating any policy on Competition or any other matter may make reference to the Commission.

K - भारत के संविधान की फ्रांस के संविधान से तुलना कीजिए।

इसे निम्न बिन्दु के आधार पर लिखा जा सकता है।

– भारत में संघात्मक प्रणाली वहीं फ्रांस में एकात्मक प्रणाली हे।

– फ्रांस की कार्यपालिका दोहरी कार्यपालिका है। जबकि भारत में संसदीय प्रणाली है।

– फ्रांस में संसद की शक्तियां कम है। जबकि भारत में संसद की विधायिका के रूप में कार्य करती है।

– फ्रांस द्वितीयक पूर्ण बहुमत प्रणाली या दूबारा मतदान प्रणाली है। जबकि भारत में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एवं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट पद्धति है।

– फ्रांस में एक व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचित पदों पर रह सकता है जबकि भारत में ऐसा नहीं है।

– फ्रांस की न्यायपालिका भारतीय न्यायपालिका से कमजोर है। आदि।

K. Compare the constitution of France with the constitution of India.

1. Written Constitution

- France :-The present French constitution which established the Fifth republic is a written constitution.
- India :- Written and longest known constitution.

2. Flexible or Rigid

- France :- Rigid constitution- needs special procedure -60% majority votes in both the house of parliament is needed.
- India :-Constitution is more flexible than rigid.

3. Unitary or Federal

- France :- It is a unitary state.
- India :- It is federal system with unitary bias.

4. Type of Government

- France :- Has quasi presidential and quasi prime ministerial.
- India :- The constitution of India provides for a parliamentary form of government both at the centre and in states.

5. President

- France :- The President is the pivot of the constitution and occupies a dominant position in the system of government. He is the real head of the state.
- India:- The President of India is the nominal head of state of the Republic of India.

6. Citizenship

- France :-Dual citizenship has been permitted since 1973.
- India :- The Indian citizenship and nationality law and the constitution of India provide single citizenship for all India.

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone

L- भारतीय संविधान संघ एवं राज्यों के बीच बटवांरा कैसे निश्चित करता है ?

संघ–राज्य संबंध

भारतीय संविधान में संघात्मक लक्षण विद्यमान हैं। संविधान में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई है। यहां संघ व राज्यों में समानान्तर सरकारें हैं जो संविधान में निर्धारित सीमाओं सीमाओं के अंतर्गत अपनी–अपनी शक्तियों का प्रयोग करती हैं। संविधान में संघ व राज्यों की शक्तियों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है तथा संघ राज्य संबंध की व्याख्या की गई है। संविधान सभा में बहस के दौरान डॉ. अम्बेडकर ने कहा था, ''हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि संघ तथा राज्यों के बीच विधायी तथा कार्यपालिका शक्ति का विभाजन संघीय सरकार के कानून द्वारा नहीं, वरन् संविधान के द्वारा किया गया है, अतः किसी भी प्रकार, राज्य अपनी शक्तियों के लिए केन्द्र पर निर्भर नहीं है।''

संविधान में संघ तथा राज्यों के बीच तीन प्रकार के संबंधों का वर्णन है–

1. विधायी संबंध, भाग 11, अनुच्छेद 245–255
2. प्रशासनिक संबंध, भाग 11, अनुच्छेद 256–263
3. वित्तीय संबंध, भाग 12, अनुच्छेद 264–300

अनुच्छेद 246 में केन्द्र व राज्य की विधायी शक्तियों का विभाजन संविधान की 7 वीं अनुसूची के अनुसार किया गया है। 7 वीं अनुसूची को 3 भागों में बांटा गया है–

1. **संघ सूची–** संसद को 7 वीं अनुसूची के सूची 1 (संघ सूची) में वर्णित विषयों पर विधि बनाने की अनन्य शक्ति है। संघसूची में राष्ट्रीय महत्व के 97 विषय वर्णित हैं जिन पर केवल संघीय संसद ही कानून बना सकती है।
2. **राज्य सूची–** राज्य विधान मंडल को 7 वीं अनुसूची के सूची 2 (राज्य सूची) में वर्णित विषयों पर विधि बनाने की अनन्य शक्ति है। राज्य सूची में क्षेत्रीय महत्व के 66 विषयों को रखा गया है।
3. **समवर्ती सूची–** 7 वीं अनुसूची के सूची–3 (समवर्ती सूची) में वर्णित विषयों पर संसद तथा राज्य विधानमंडल, दोनों को विधि बनाने की शक्ति है। परन्तु यदि राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून संसद द्वारा बनाये गये कानून का विरोधाभासी है तो, राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून विरोधी की मात्रा तक शून्य समझा जाएगा, चाहे वह संघीय कानून के पहले बनाया गया हो या बाद में (अनुच्छेद 256)। परन्तु यदि समवर्ती सूची के विषय में राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि को राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाती है, तो वह विधि संबंधित राज्य में प्रभावी होगी। समवर्ती सूची में 47 विषय रखे गए हैं।

L. How has the constitution of India ensured the division of Power between the Centre and the States?

The division of power between the Central and State Governments is done in a three fold distribution of legislative powers between the Union and the State Governments.

There are three lists - Union List, State List and Concurrent List.

1. Union List: It includes subjects of national importance, e.g., defence of the country, foreign affairs, banking, communication and currency. The Central Government alone can make decisions on these matters.

   The aim of including these matters in Union List is to ensure uniformity in the policy of these areas throughout the country.
2. State List: It consists subjects of state and local importance such as police, trade, commerce, agriculture and irrigation. The State Governments alone can make laws and decisions on these areas.
3. Concurrent List: It includes those subjects which are of common interest to both the Central as well as State Governments. It includes matters like education, forests, marriage and trade unions. Both the State and Central Governments can make decision on these matters.

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone
KAUTILYA ACADEMY INDORE

PART- A 15 Marks

A- केन्द्र–राज्य संबंधो के तनाव संभाव्य क्षेत्रों का वर्णन करें।

इस उत्तर को निम्न तनाव संभाव्य क्षेत्रों की व्याख्या कर लिखा जा सकता है।

- राष्ट्रपति शासन 356
- राज्यपाल की भूमिका।
- राज्य में कानून व्यवस्था पर बिगड़ने पर केन्द्र द्वारा सशस्त्र बलों को भेजने की शक्ति देना।
- वित्तीय आवांटन
- अखिल भारतीय सेवाएं
- अनुच्छेद 249
- कानून व्यवस्था बिगड़ने पर केन्द्र सरकार का राज्यों को निर्देश भेजना।
- आर्थिक आयोजन
- राजनीतिक कारक
- मीडिया का दुरूपयोग
- सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल
- राज्यों की स्वायत्तता एवं विशेष दर्जे की मांग आदि।

इसके अलावा आप समसमायिक घटनाओं के माध्यम से तनाव क्षेत्र का वर्णन कर सकते हैं। जैसे– सी ए ए, एन पी आर आदि।

B- भारत में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की संरचना एवं कार्यों की विवेचना कीजिए?

अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए एक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (National Commission for Scheduled Castes) का प्रावधान है जबकि 89 वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा जोड़े गये अनुच्छेद 338 क द्वारा एक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (National Commission for Scheduled Tribes) का उपबंध किया गया है। आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा तीन सदस्य होंगे जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। उनकी सेवा शर्तों तथा पदावधि का निर्धारण भी राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा परन्तु आयोग अपनी प्रक्रिया का निर्धारण भी राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। परन्तु आयोग अपनी प्रक्रिया स्वयं निर्धारित करेगा।

A. What are some of the tension areas between the centre and the State?

The issues which created tensions and conflicts between the Centre and states are:

1. Mode of appointment and dismissal of governor;
2. Discriminatory and partisan role of governors;
3. Imposition of President's Rule for partisan interests;
4. Deployment of Central forces in the states to maintain law and order;
5. Reservation of state bills for the consideration of the President;
6. Discrimination in financial allocations to the states;
7. Role of Planning Commission in approving state projects;
8. Management of All-India Services (IAS, IPS, and IFS);
9. Use of electronic media for political purposes;
10. Appointment of enquiry commissions against the chief ministers;
11. Sharing of finances (between Centre and states); and
12. Encroachment by the Centre on the State List. (Explain points in detail)

B. Explain the structure and functions of the National Commission for the Scheduled Tribes in India.

Introduction :- Article 366 (25) of the Constitution of India refers to Scheduled Tribes as those communities, who are scheduled in accordance with Article 342 of the Constitution. This Article says that only those communities who have been declared as such by the President through an initial public notification or through a subsequent amending Act of Parliament will be considered to be Scheduled Tribes.

338 A states that there shall be a Commission for the Scheduled Tribes to be known as the National Commission for the Scheduled Tribes.

Structure:- The term of office of Chairperson, Vice-Chairperson and each member in the National Commission of SC's is three years from

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone

राष्ट्रपति आयोग के प्रतिवेदन को संघ द्वारा की गई कार्रवाइयों के साथ संसद के दोनों के समक्ष रखवाएगा। प्रतिवेदन में राज्यों से संबंधित सिफारिश उस राज्य के राज्यपाल को भेजी जाएगी। राज्यपाल ऐसे प्रतिवेदन को राज्यों द्वारा द्वारा की गई सिफारिशों के साथ राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। प्रतिवेदन में की गई किसी सिफारिश को स्वीकृत करने पर स्वीकृति का कारण भी दिया जाएगा।

राष्ट्रपति अनुसूचित जाति आयोग के कार्य

1. अनुसूचित जाति से संबंधित विषयों का अन्वेषण करना, उन पर निगरानी रखना तथा ऐसे रक्षोपाय के कार्यकरण का मूल्यांकन करना।
2. अनुसूचित जातियों के अधिकारों और रक्षोपाय से वंचित करने की शिकायतों की जांच करना।
3. अनुसूचित जातियों के सामाजिक–आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना, उन पर सलाह देना तथाा प्रगति का मूल्यांकन करना।
4. रक्षोपाय के कार्यकरण के बारे में राष्ट्रपति को प्रतिवर्ष प्रतिवेदन देना।
5. रक्षोपाय के प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करना।
6. अनुसूति जातियों के संरक्षण, कल्याण, विकास एवं उन्नयन के बारे में राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य करना।

the date of assumption of charge. The Chairperson has been given the rank of Union Cabinet Minister, and the Vice-Chairperson that of a Minister of State and other Members have the ranks of a Secretary to the Government of India.

Functions of the Commission:

(a) To investigate and monitor all matters relating to the safeguards provided for the Scheduled Tribes under this Constitution or under any other law for the time being in force or under any order of the Government and to evaluate the working of such safeguards;

(b) To participate and advise on the planning process of socioeconomic development of the Scheduled Tribes and to evaluate the progress of their development under the Union and any State;

(c) to make in such reports recommendation as to the measures that should be taken by the Union or any State for the effective implementation of those safeguards and other measures for the protection, welfare and socio-economic development of the Scheduled Tribes; and

(d) Measures that need to be taken over conferring ownership rights in respect of minor forest produce to the Scheduled Tribes living in forest areas.

(e) Measures to be taken to safeguard rights to the Tribal Communities over mineral resources, water resources etc. as per law.

(f) Measures to be taken for the development of tribes and to work for more viable livelihood strategies.

C - राज्यों में कार्यरत ग्रामीण स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के कार्यकरण व समस्याओं पर एक आलोचनात्मक लेख लिखिए।

हयू ग्रे का मानना है कि ''पंचायती राज हो या न हो प्रश्न यह नहीं है बल्कि यह लोकतंत्र हो या न हो, यह प्रश्न है।'' यदि हम लोकतंत्र के सिद्धांतों के लिए समर्पित हैं तो स्थानीय स्तर पर स्वशासी संस्थाएं आवश्यक हैं। भारत में पंचायती राज संस्थाएं लोकतंत्र की बुनियाद हैं। इसकी सफलता ही लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करेगी। इसके अंतर्गत अधिकाधिक लोक सत्ता में भागीदारी कर सकेंगे, जिससे समाज का सर्वांगीण विकास होने के साथ–साथ लोकतांत्रिक ताने–बाने को भी नया आयाम दिया जा सकेगा।

C. Write a critical note on the working and problems of Rural Local Self Government in the States.

Local government is government at the village and district level. Local government is about government closest to the common people. Local government is the government that involves the day-to-day life and problems of ordinary citizens. Local government believes that local knowledge and local interest are essential ingredients for democratic decision making. They are also necessary for efficient and people-friendly administration. The advantage of local government is that it is so near the people. It is convenient for the people to approach the local

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone

यहां यह बात उल्लेखनीय है कि आजादी के वर्तमान परिवेश में इस स्वशासी संस्था को ढेर सारी समस्याओं से जुझना पड़ रहा है जिनका उल्लेख इस प्रकार हैः

1. पंचायती राज की अवधारणा काफी संकीर्ण है।
2. शासक वर्ग में पारदर्शिता और इच्छा शक्ति का अभाव
3. तीसरी बड़ी समस्या है, भारत के ग्रामों का सामाजिक वातावरण। ग्रामीण समाज न केवल अशिक्षित व रूढ़िवादी है बल्कि जाति प्रथा में जकड़ा हुआ है। परिणामतः लोगों में अवसरों तथा अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता का अभाव देखने को मिलता है।
4. पंचायतों पर धनी और शक्तिशाली, प्रभावशाली लोगों का वर्चस्व भी एक गंभीर समस्या रही है। परिणामतः प्रतिनिधि संस्थाओं का उद्देश्य समाज का सर्वांगीण विकास की अवधारणा मूलतः नष्ट हो जाती है।
5. भ्रष्टाचार, हिंसा तथा पंचायती चुनाव में 'रूडल्फ एवं रूडल्फ' के शब्दों में धन एवं शक्ति के वर्चस्व ने लोकतंत्र की इस बुनियादी इकाई को बेमानी बना दिया है। इससे लोगों की जनसहभागिता जो स्वशासी संस्था का केन्द्र बिन्दु हैं, गंभीर तरीके से प्रभावित होती है।
6. इसी क्रम में पंचायतों के प्रति नौकरशाही का नकारात्मक रवैया एक अवरोधक का काम करता है।
7. वित्तीय संसाधनों की कमी पंचायती संस्थाओं की बहुत बड़ी कमजोरी है। राज्य वित्तीय आयोग होने के बावजूद पंचायती संस्थान धन के अभाव से ग्रसित रहते हैं। आदि।

D - भारत में चुनाव सुधारों की जानकारी दीजिये, एवं बेहतर चुनाव प्रणाली के लिए सुझाव दीजिए।

चुनाव सुधार वास्तव में तीन बिन्दुओं पर आधारित है।

1. चुनाव आयोग 2. राजनीतिक दल
3. मतदाता

उपरोक्त तीनों में सुधार करके ही चुनाव में सुधार किया जा सकता है। अभी तक किये गये सुधारों का वर्णन करें। जैसे– इलेक्ट्रॉनिक बोटिंग मशीन का प्रयोग। मत देने की आयु कम करना। मतदाता फोटो पहचान पत्र, शराब बिक्री पर रोक। चुनाव प्रचार की अवधि में कमी (14 दिन), इलेक्शन बोंड, वी वी पी ए टी का प्रयोग निर्वाचन खर्च में वृद्धि, एक्जिट पोल पर प्रतिबंधा, नोटा का प्रयोग आदि।

सुझाव–

government for solving their problems both quickly and with minimum cost. However, the system of Local Self-Government is not completely without any defect or drawback.

The problems of Local Self-Government are discussed below-

1. Finance Scarcity
2. Unplanned urbanization
3. Excessive State Control-
4. Low Effectiveness
5. Multiplicity of Agencies
6. Substandard Personnel
7. Low level of People's Participation
8. Regionalism
9. Lack of cordial relation between officials and people
10. Administrative Problem (Explain points)

D. Write a short note on the electoral reforms which have been undertaken in India. Give suggestions to improve the electoral system in India.

Electoral reforms:- It refer to the introduction of the best practices in ensuring better democracy, clean politics, fair elections, ideal members of legislative houses, true representation and so on. The process of electoral reforms focuses mainly on broadening the core meaning of democracy, making it more citizen-friendly.

Following are the Constitutional articles related to electoral reforms:

1. Article 324-329 deals with elections and electoral reforms.

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone

- जमानत राशि में वृद्धि की जायें।
- पेड न्यूज एवं फेक न्यूज पर रोक लगाई जाये।
- सरकार द्वारा प्रयोजित विज्ञापनों पर रोक लगाई जायें
- राजनीतिक दलों के अपंजीकरण का अधिकार चुनाव आयोग को दिया जाये।
- दलो के भीरत आन्तरिक लोकतंत्र का निर्माण किया जाये।
- दोषी सिद्ध होने पर सदस्यता निरस्त कर दी जाये।
- टोटलाइजर का प्रयोग हो।
- मतदान अनिवार्य किया जायें।
- राइट टू रिकॉल का लागू किया जाये। आदि।

2. Article 324 deals with the Superintendence, direction, and control of elections to be vested in an Election Commission.
3. Article 325 states that no person to be ineligible for inclusion in or to claim to be included in a special, electoral roll on grounds of religion, race, caste or sex. Article 326 deals with the Elections to the House of the People and to the Legislative Assemblies of States to be on the basis of adult suffrage.
5. Article 327 provides power to the Parliament to make provision with respect to elections to Legislatures.
6. Article 328 provides power to Legislature of a State to make provision with respect to elections to such Legislature.
7. Article 329 provides to create a bar on the court to make any interference by courts relating to electoral matters.

The Electoral reforms contain the following aspects:

1. Transparency about the background of the candidates
2. Freeing the election processes from muscle and money power
3. Prohibiting the nexus between business and politics.

Suggestions for improvement in Indian electoral system:-

1. First pass the Post (FPTP) system should be replaced with Proportional Representation system.
2. First Pass the Post electoral process can be replaced with two stage electoral process.
3. There should be simultaneous elections to Lok Sabha and Vidhan Sabha.
4. There is a need to limit the number of political parties in country.
5. Increase security deposit to discourage non-serious members from fighting the elections.
6. Candidates should be allowed to fight elections from single constituency.
7. Criminalisation of politics should be checked.

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone

PART- B

A- कुपोषण के कारण–

– फोलिक एसिड की कमी

– विटामिन–बी12 की कमी

– लौह तत्व की कमी

– भोजन में अनियमित्ता। आदि।

B- निर्भय कोष–

– देश की सामूहिक चेतना को हिला कर रख देने वाले निर्भया कांड के बाद महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक कोष की जरूरत महसूस की गई. जिस पर संज्ञान लेते हुए तत्कालीन यूपीए सरकार ने 2013 के बजट में निर्भया फंड की घोषणा की. वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने शुरुआती तौर पर 1000 करोड़ का आवंटन भी किया. 2014–15 और 2016–17 में एक–एक हजार करोड़ और आवंटित किए गए।

C- मानव संसाधन विकास–

मानव संसाधन वह अवधारणा है जो जनसंख्या को अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में देखती हैं। शिक्षा प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश के परिणाम स्वरूप जनसंख्या मानव संसाधन के रूप में बदल जाती है। मानव संसाधन उत्पादन में प्रयुक्त हो सकने वाली पूँजी है। यह मानव पूँजी कौशल और उन्में निहित उत्पादन के ज्ञान का भंडार है। यह प्रतिभाशाली और काम पर लगे हुए लोगों और संगठनात्मक सफलता के बीच की कड़ी को पहचानने का सूत्र है। यह उद्योगध संगठनात्मक मनोविज्ञान और सिद्धांत प्रणाली संबंधित अवधारणाओं से संबद्ध है। मानव संसाधन की संदर्भ के आधार पर दो व्याख्याएं मिलती हैं।

D- WHO किस वर्ष स्थापित किया गया–

– 07 अप्रैल, 1948।

E- NCOV-2019-

2019 नोवेल कोरोना वायरस जो वुहान कोरोना वायरस भी कहलाता है। यह एक प्रकार का वायरस(विषाणु) है जो श्वसन तंत्र संक्रमण उत्पन्न करता है और मानव–से–मानव में फैलता है। इसकी पहवान सर्वप्रथम 2019–20 में वूहान, हूबेई, चीन में करी गई थी, जहाँ यह 2019–20 वुहान कोरोना वायरस प्रकोप का कारक था।

A. Causes of Malnutrition

- Malnutrition is a condition that results from nutrient deficiency or overconsumption. Types of malnutrition include -
- Undernutrition: This type of malnutrition results from not getting enough protein, calories or micronutrients.
- Overnutrition: Overconsumption of certain nutrients, such as protein, calories or fat.

B. NIRBHAYA FUND

The Nirbhaya Fund Framework provides for a non-lapsable corpus fund for safety and security of women to be administered by the Department of Economic Affairs (DEA) of the Ministry of Finance (MoF) of the Government of India. Further, it provides for an Empowered Committee (EC) of officers chaired by the Secretary, Ministry of Women & Child Development (MWCD) to appraise and recommend proposals to be funded under this framework.

C. Define Human Resource Development

- Human resources development (HRD) refers to the vast field of training and development provided by organizations to increase the knowledge, skills, education, and abilities of their employees.

D. In which year was W.H.O formed?

- 7th April 1948

E. ncov-2019

- 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) is a virus identified as the cause of an outbreak of respiratory illness first detected in Wuhan, China.

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone

F- NCVT–

– नेशनल कौंसिल फार वुकेशनल ट्रेनिंग इसका गठन 1956 में व्यवसायिक शिक्षा के प्रशिक्षण मानक एवं उसके पाठ्यक्रम को निर्धारित करने में सरकार को सलाहे देती है। नीति निर्माण कार्यक्रम परिक्षाओं का संचालन करती है।

G- संक्रमक बीमारियों के पांच उदाहरण–

– छोटी माता, चेचक, हैजा, डेंगू ज्वर, सूजाक, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई, इन्फ्लुएंजा, कुष्ट रोग, मलेरिया, खसरा, तानिकाशोथ, प्लेग, उपदंश, टेटनस, क्षय, पीत ज्वर।

H- बॉयो–टेक्नोलॉजी–

– बायो यानी जीवित प्रणाली और टेक्नोलॉजी मतलब तकनीक। इसके मुताबिक बायोटेक्नोलॉजी का मतलब है जीवित प्राणियों पर तकनीक का इस्तेमाल करना।

I- राष्ट्रीय वयोश्री योजना–

– वरिष्ठ नागरिकों को शारीरिक सहायता एवं जीवन यापन के लिये आवश्यक उपकरण प्रदान करने वाली 'राष्ट्रीय वयोश्री योजना' का शुभारंभ आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में 01 अप्रैल 2017 को किया जाएगा। ये सहायक उपकरण उच्च गुणवत्ता से युक्त होंगे और इन उपकरणों को भारत मानक ब्यूरो द्वारा तय मापदंडों के अनुसार तैयार किया जाएगा। यह सार्वजनिक क्षेत्र की केन्द्रीय योजना है, जिसके लिये पूर्ण रूप से केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान दिया जाएगा।

J- श्रमविभाजन–

– जब किसी बड़े कार्य को छोटे–छोटे तर्कसंगत टुकड़ों में बाँटककर हर भाग को करने के लिये अलग–अलग लोग निर्धारित किये जाते हैं तो इसे श्रम विभाजन या विशिष्टीकरण कहते हैं। श्रम विभाजन बड़े कार्य को दक्षता पूर्वक करने में सहायक होता है। ऐतिहासिक रूप से श्रम–विभाजन व्यापार की वृद्धि, सम्पूर्ण आउटपुट की वृद्धि, पूंजीवाद का उदय तथा औद्योगीकरण की जटिलता में वृद्धि से जुड़ा रहा है। परिष्कृत होकर धीरे–धीरे श्रम–विभाजन वैज्ञानिक प्रबन्धन के स्तर तक जा पहुँचा। मोटे तौर पर यह कार्यकारी–समाज है जिसके अलग–अलग भाग भिन्न–भिन्न काम करते हैं।

F. NCVT

- The National Council for Vocational Training, an advisory body, was set up by the Government of India in 1956
- The Council has been entrusted with the responsibilities of prescribing standards and curricula for craftsmen training, advising the Government of India on the overall policy and programs, conducting All India Trade Tests and awarding National Trade Certificates.

G. Give five examples of Communicable diseases-

- HIV, hepatitis A, B and C, measles, influenza, Rabies

H. What is Bio-Technology?

- Biotechnology means any technological application that uses biological systems or living organisms to make or modify products or processes for specific use.
- It refers to the use of microorganisms such as bacteria, yeasts, or biological substances such as enzymes, to perform specific industrial or manufacturing processes.

I. Rashtriya Vayoshri Yojna

- Is a scheme for providing Physical Aids and Assisted-living Devices for Senior citizens belonging to BPL category.
- This is a Central Sector Scheme, fully funded by the Central Government.
- The expenditure for implementation of the scheme will be met from the "Senior Citizens' Welfare Fund".

J. What is division of labour?

- Division of Labour means that the main process of production is split up into many simple parts and each part is taken by different workers who are specialised in the production of that specific part.

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone
KAUTILYA ACADEMY INDORE

जैसे– कुछ लोग कृषि करते हैंय कुछ लोग कुम्भकारी करते हैं और कुछ लोग लोहारी करते हैं। भारत की वर्णाश्रम व्यवस्था मूलतः श्रम–विभाजन का ही रूप है।

K- RUSA-

– राष्ट्रीय उच्च्चतर शिक्षा अभियान भारत सरकार की एक प्रायोजित योजना है जिसे राज्यों के पात्र उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं को वित्तपोषित करने के उद्देश्य से वर्ष 2013 में प्रारंभ किया गया था। इस योजना का उद्देश्य है रोजगार योग्यता में सुधार के लिए प्रासंगिक और मूल्य आधारित शिक्षा प्रदान करना है इस योजना के द्वारा व्यक्ति को ज्ञान, व्यवहार एवं कौशल की सकारात्मक शिक्षा के माध्यम से प्रभावित करने का प्रयास किया जाना परिकल्पित है।

K. RUSA

- Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan (RUSA) is a Centrally Sponsored Scheme (CSS), launched in 2013 aims at providing strategic funding to eligible state higher educational institutions.

L- मुक्त विश्वविद्यालय–

– ऐसे विश्वविद्यालय होते हैं जो दूरस्थ शिक्षा के उद्देश्य से स्थापित किये जाते हैं। ऐसे विश्वविद्यालय भारत, यूके तथा अन्य देशों में कार्य कर रहे हैं। इन विश्वविद्यालयों में प्रवेश नामांकन की नीति खुली या शिथिल होती हैं।

उद्देश्य–

(क) देरी से पढ़ाई शुरू करने वालों,

(ख) जिन व्यक्तियों के घर के पास उच्चतम शिक्षा साधन नहीं है,

(ग) सेवारत व्यक्तियों और

(घ) अपनी शैक्षिक योग्यताएं बढ़ाने के इच्छुक व्यक्तियों को लाभ प्रदान कर रही है।

L. What is Open University?

- Open Universities provide education through open-door academic policy.
- These universities follow no-class room teaching method.
- Fees is affordable

M- सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी–

– सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (देवनागरीः सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी) भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए भारतीय राष्ट्रीय संस्थान हैं। इस प्रशिक्षण के बाद इन अधिकारियों को उनकी ड्यूटी करने के लिए सम्बंधित भारतीय राज्य कैडर (उच्च प्रशिक्षण प्राप्त सैनिकों, कर्मचारियों का समूह) में भेज दिया जाता है। यह अकादमी हैदराबाद, भारत में स्थित है।

M. Sardar Vallabh Bahi Patel National Police Academy

- The Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy (SVPNPA), trains officers of the Indian Police Service, who have been selected through an All India based Civil Services Examination.

N- R.C.E.P–

– RCEP एक फ्री ट्रेड पैक्ट हैं, जिसके तहत सदस्य देश एक दूसरे से आयात और निर्यात पर बहुत कम टैक्स लगाते हैं। इस समझौते में आसियान के 10 सदस्य देशों के अलावा भारत, चीन, जापान, साउथ कोरिया,

N. R.C.E.P

- The Regional Comprehensive Economic Partnership was introduced during the 19th Asean meet held in November 2011.

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone

ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं।

- RCEP aims to create an integrated market with 16 countries, making it easier for products and services of each of these countries to be available across this region.
- The negotiations are focused on the following: Trade in goods and services, investment, intellectual property, dispute settlement, e-commerce, small and medium enterprises, and economic cooperation.

O- BIMSTEC–

– बिम्सटेक जिसका पूरा रूप बंगाल की खाड़ी बहु–क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग उपक्रम है, बंगाल की खाड़ी से तटवर्ती या समीपी देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है। इसमें नवम्बर 2016 में बांग्लादेश, भारत, बर्मा, श्रीलंका, थाईलैण्ड, भूटान और नेपाल सदस्य थे। पाकिस्तान इसका सदस्य नहीं है।

इस संगठन का उद्देश्य तीव्र आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देना और साझा हितों के मुद्दों पर समन्वय स्थापित करने के लिए सदस्य देशों के बीच सकारात्मक वातावरण बनाना है।

O. BIMSTEC

- The Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation is a regional organization comprising seven Member States lying in the littoral and adjacent areas of the Bay of Bengal constituting a contiguous regional unity. This sub-regional organization came into being on 6 June 1997 through the Bangkok Declaration. It constitutes seven Member States: five deriving from South Asia, including Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, Sri Lanka, and two from Southeast Asia, including Myanmar and Thailand.

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone
KAUTILYA ACADEMY
INDORE

A. Write a short note on Sarva Shiksha Abhiyan?

PART- B 6 Marks

A- सर्वशिक्षा अभियान पर संक्षिप्त टिप्पणी–

– सर्व शिक्षा अभियान 2001 भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसकी शुरूआत (2001–02) मे अटल बिहारी बाजपेयी द्वारा एक निश्चित समयावधि के तरीके से प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण जैसा कि भारतीय संविधान के 86वें संशोधन द्वारा निर्देशित किया गया है जिसके तहत 6–14 साल के बच्चों (2001 में 205 मिलियन अनुमानित) की मुफ्त और अनिवार्य

2003 तक सभी स्कूल में हों।2007 तक प्राथमिक शिक्षा का 5 साल पूरा करना और 2010 तक स्कूली शिक्षा का 8 साल पूरा करना।संतोषजनक गुणवत्ता और जीवन के लिए शिक्षा पर बल देना 2007 तक प्राथमिक स्तर पर और 2010 तक प्रारंभिक स्तर पर सभी लैंगिक और सामाजिक अंतर को समाप्त करना। वर्ष 2010 तक सार्वभौमिक प्रतिधारण सर्व शिक्षा अभियान

Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) is Government of India's flagship programme for achievement of Universalization of Elementary Education (UEE) in a time bound manner, as mandated by 86th amendment to the Constitution of India making free and compulsory Education to the Children of 6-14 years age group, a Fundamental Right.

SSA is being implemented in partnership with State Governments to cover the entire country and address the needs of 192 million children in 1.1 million habitations.

The programme seeks to open new schools in those habitations which do not have schooling facilities and strengthen existing school infrastructure through provision of additional class rooms, toilets, drinking water, maintenance grant and school improvement grants.

Existing schools with inadequate teacher strength are provided with additional teachers, while the capacity of existing teachers is being strengthened by extensive training, grants for developing teaching-learning materials and strengthening of the academic support structure at a cluster, block and district level.

SSA seeks to provide quality elementary education including life skills. SSA has a special focus on girl's education and children with special needs. SSA also seeks to provide computer education to bR&Dge the digital divide.

B- कुपोषण को समाप्त करने के लिए चलाई गई योजनाएं–

1. राष्ट्रीय पोषण नीति, 1993
2. समन्वय, बालविकास योजना, 1975
3. मिड डे मील
4. आंगनवाड़ी योजना
5. रेपिड सर्वे ऑन चिल्ड्रन
6. एकीकृत बाल विकास सेवा
7. अटल बार आरोग्य मिशन
8. प्रोजेक्ट शक्तिमान
9. सबला योजना
10. लालिमा योजना आदि।

B. Write the programs for the allevation of malnutrition.

1. Integrated Child Development Scheme (ICDS).
2. National Rural Health Mission(NRHM).
3. Rajiv Gandhi National Creche Scheme.
4. National Rural Drinking Water Progrrame (NRDWP).
5. Total Sanitation Campaign (TSC).
6. Kishori Shakti Yojna
7. Mid-Day Meals.

C. Give information about the Higher Educational Institutes in Madhya Pradesh.

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone
KAUTILYA ACADEMY INDORE

C- म.प्र. में स्थित उच्च शिक्षा संस्थानों की जानकारी–

– उच्च शिक्षा संस्थान ज्ञान, कौशल प्रदान करने के साथ–साथ व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाते हैं। मध्यप्रदेश में 1946 में हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर की स्थापना की बाद उच्च शिक्षा की शुरूआत हुई।

म.प्र. में प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थान निम्न है।

– अटल बिहारी बाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय भोपाल
– लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर
– राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय भोपाल
– महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय सतना
– राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय भोपाल
– राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल
– महर्षि पाणिनी संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन
– राजा मानसिंह तोमर संगीत कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर
– नाना जी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय जबलपुर
– महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय छतरपुर
– डॉ. भीम राव अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान इंदौर आदि

I. State Universities

1. Awadesh Pratap Singh University, Rewa
2. Barkatullah University, Bhopal
3. Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore.
4. Jawaharlal Nehru Krishi Vishwavidyalaya, Jabalpur
5. Jiwaji University, Gwalior
6. M.G. Gramodaya Vishwavidyalaya, Chitrakoot, District Satna.
7. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya, Jabalpur
8. M.P.Bhoj (open) University, Bhopal
9. Makhanlal Chaturvedi Rashtriya Patrakarita National University of Journalism, Bhopal
10. Maharishi Panini Sanskrit Vishwavidyalaya, Ujjain

II. Central Universities

1. The Indira Gandhi National Tribal University, Amarkantak, Madhya Pradesh
2. Dr. Harisingh Gour Vishwavidyalaya, Sagar, Madhya Pradesh

III. Deemed Universities

1. Indian Institute of Information Technology and Management Gola Ka Mandir, Gwalior, M.P.
2. Lakshmibai National Institute of Physical Education Shakti Nagar, Gwalior.M.P.
3. Pandit Dwarka Prasad Mishra Indian Institute of Information Technology, Design & Manufacturing(PDPM-IIITDM) IT Bhawan, Government Engineering College, Jabalpur Madhya Pradesh.

IV. Private Universities

1. Jaypee University of Engineering & Technology AB Road, Raghogarh, Distt, Guna,Madya Pradesh

V. Educational Regulatory Authorities

1. Academy of Administration and Management, Bhopal
2. Board of Secondary Education, Madhya Pradesh
3. Department of Higher Education, Government of Madhya Pradesh, Bhopal
4. Madhya Pradesh State Co-operative Union Limited (MPSCU), Bhopal, Madhya Pradesh.
5. Directorate of Technical Education, Government of Madhya Pradesh, Bhopal.

D. What is the difference between All India Services and Central Services.

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone

D- अखिल भारतीय सेवा एवं केन्द्रीय सेवाओं में अंतर–

अखिल भारतीय सेवा

– अखिल भारतीय सेवायें राज्य एवं केन्द्र के अधीन कार्यरत सेवाएं है। इसे तीन भागों में बांटा गया है।

1. भारतीय प्रशासनिक सेवा
2. भारतीय वन सेवा
3. भारतीय पुलिस सेवा।

केन्द्रीय सेवा

– केन्द्रीय सेवा केवल केन्द्र सरकार के अधीन कार्यरत सेवा है। इसके अन्तर्गत विभिन्न विभागों में विशिष्ट पदो पर सेवायें दी जाती है।

There are only three All India Services namely Indian Administrative Service [IAS], Indian Police Service [IPS] and Indian Forest Service [IFS].

The officers of these services are allotted a state [called as cadre state] and have to work in that state government only till retirement. However, they can also work for Government of India at its Central Secretariat in New Delhi while on deputation for some years.

On the other hand, there are too many Central Civil Services namely Indian Revenue Service, Indian Information Service, Indian Customs & Central Excise Service, Indian Postal Service, Indian Audit & Accounts Service, Indian Defence Estates Service, Indian Defence Accounts Service, Indian Civil Accounts Service, Indian Railway Traffic Service, Indian Railway Accounts Service, Indian Railway Personnel Service, Indian Trade Service, etc.

The officers of these services are not allotted any state in particular and can be transferred from one part of the country to other place. They can't work for any state government and work for Government of India only till retirement. In some rare cases, some of these officers can go on deputation to any state government [mostly in their native state and on personal request of the particular officer only] and work in any ministry in that state government.

E- पर्यावरण अधिनियम 1986 पर्यावरण बचाने के लिए काफी है–

इस प्रश्न का उत्तर निम्न प्रकार से लिखें।

– पर्यावरण अधिनियम 1986 के उद्देश्य व मुख्य प्रावधान लगभग 40 शब्दों में लिखे।

– इसकी सीमाओं का उल्लेख करें। जैसे– प्रक्रिया में देरी, प्रभावी नियंत्रण का अभाव आदि।

– अन्त में सुझाव दें एवं निष्कर्ष के रूप में लिखें कि पर्यावरण की रक्षा कानूनों के साथ–साथ जनभागीदारी और इसके महत्व के प्रति लोगों को संवदेनशील बनाने की है। तब कहीं इस प्रकृति की एवं मानव की रक्षा हो सकेंगी।

E. Is the Environment (Protection) Act, 1986 enough to save the environment?

Though we have significant Environmental protection laws in India, we have not been very successful in fulfilling the requirements of environmental protection, mainly due to the absence of political will and public awareness. Another reason may be because most of our environmental laws are human centric i.e. primarily focusing on the protection of humans and benefit them and not explicitly meant for the protection of the environment in which humans live. The possible reason behind this is the fact that almost all environmental laws consider the superiority of humans over nature and ecosystem. On the other hand, the ecosystem is a complex system which is closely integrated and self–regulating. It works best when left alone by human interventions whereas our laws are

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone

particularly concerned with enhancing the economic welfare of human beings.

F. Why is the SAARC failing?

South Asian Association for regional cooperation (SAARC) headquartered in Kathmandu, Nepal aims for integration of south Asian nations for undertaking collective efforts to achieve common objective of regional stability and prosperity.

SAARC has failed in achieving its objectives because:

1. India-Pakistan rivalry has become a bottleneck in achieving effective coordination. Last SAARC summit got cancelled because of the Indo-Pak tensions.
2. Even though the region accounts for 21% of world population, its share in global GDP is just around 3%. Being one of the poverty ridden areas of the world, there is limited avenues to achieve synergy.
3. Almost every member is facing numerous internal crisis like Tamils issue in Srilanka, Constitutional crisis in Nepal, religious fundamentalism in Pakistan and Bangladesh, Terrorism and instability in Afghanistan.
4. Long pending issues between members like fishermen issue between India and Srilanka, Teesta water sharing between India and Bangladesh, lack of direct access to Afghanistan to other members except Pakistan have restricted in arriving at common ground for regional integration and also resulted in increased mistrust among the members.

F- सार्क की असफलता के कारण–

1. दक्षिण देशों की कम भागीदारी।
2. भारत पाकिस्तान विवाद।
3. सदस्या देशों का क्षेत्रीय विकास।
4. सदस्य देशों का सामाजिक विकास।
5. सदस्य देशों की विश्व अर्थव्यवस्था में कम भागीदारी।
6. भारत की भूमिका
7. बिम्स्टेक का बढ़ता महत्व
8. पाकिस्तान का रवैया।

G. What is the role & responsibilities of AICTE?

1. To ensure new institutes are in line with the policy and new as well as old institutes improve.
2. To help Institutions in preparing professionals (who are competent) like engineers, pharmacists, managers, architects or scientists and encourage them to think beyond the curriculum while imparting training for the advancement of knowledge.
3. To ensure approvals are done periodically in a transparent way.
4. To make the approval process easier simpler and uniform.
5. T0 emphasis on e-governance to ensure transparency, accountability,

G- AICTE की भूमिका–

– अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (All India Council for Technical Education / AICTE) भारत में नई तकनीकी संस्थाएं शुरू करने, नए पाठयक्रम शुरू करने और तकनीकी संस्थाओं में प्रवेश–क्षमता में फेरबदल करने हेतु अनुमोदन देती है। यह ऐसी संस्थाओं के लिए मानदंड भी निर्धारित करती है। इसकी स्थापना 1945 में सलाहकार निकाय के रूप में की गई थी और बाद में संसद के अधिनियम द्वारा 1987 में इसे संविधिाक दर्जा प्रदान किया गया।

– इसका मुख्यालय नयी दिल्ली में है जहाँ इसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सचिव के कार्यालय हैं। कोलकाता, चौन्नई,

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone

कानपुर, मुम्बई, चंडीगढ़, भोपाल और बंगलौर में इसके 7 क्षेत्रीय कार्यालय स्थित हैं। हैदराबाद में एक नया क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया गया है।

– यह तकनीकी संस्थाओं के प्रत्यायन या कार्यक्रमों के माध्यम से तकनीकी शिक्षा के गुणवत्ता विकास को भी सुनिश्घचित करती है। अपनी विनियामक भूमिका के अलावा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की एक बढ़ावा देने की भी भूमिका है जिसे यह तकनीकी संस्थाओं को अनुदान देकर महिलाओं, विकलांगों और समाज के कमजोर वर्गों के लिए तकनीकी शिक्षा का विकास, नवाचारी, संकाय, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने संबंधी योजनाओं के माध्यम से कार्यान्वित करती है।

H- व्यावसायिक शिक्षा–

– व्यावसायिक शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसके द्वारा किस खास विषय जैसे– कम्प्यूटर, बैंकिंग, वित्त, पर्यटन, व्यापार आदि क्षेत्रों में कुशल बनाया जाता है।

व्यावसायिक शिक्षा का महत्व

– गरीबों को अवसर प्रदान करना।
– रोजगार उत्पन्न करना।
– बेरोजगारी दूर करना।
– मित्त व्यय शिक्षा।
– उन्नत कैरियर

I- मिड–डे–मील योजना की आपूर्तियां– कमियाँ

– सत्ता द्वारा दिया गया वित्तीय आवंटन
– सभी स्कूलों में रसोई घर न होना।
– सभी जगह योजना संचालित न होना।
– खानें की गुणवत्ता
– भोजन की स्वच्छता
– योजना में सरकार की भागीदारी
– योजना में शिक्षा विभाग की लापरवाही।

6. To Implement a tech-savvy approach to enable faster processing.
7. To define clearly the infrastructural and qualification norms in Institutions.

H. What is vocational education? Why it is essential?

Vocational education is education that prepares students for work in a specific trade, a craft, as a technician, or in professional vocations such as engineering, accountancy, nursing, medicine, architecture, or law. Craft vocations – such as jewellery making, or metalwork such as those training to become silversmiths – are usually based on manual or practical activities and are traditionally non-academic, but related to a specific trade or occupation. Vocational education is sometimes referred to as career education or technical education.

With the worldwide development of economics, the labour market became more specialized. Demand of higher levels of skill both in government and business sector started increasing. This lead to the further development of vocational education through funded training organizations and subsidized apprenticeship or traineeship initiatives for business.

I. What are shortcoming's of the mid-day meal programme?

Shortcomings of the Midday meals Scheme are:-

1. Corruption is involved in the delivery system due to which children are getting low quality and insufficient food.
2. Lack of proper monitoring and supervision is also the biggest problem of this scheme.
3. Sometimes reports have found dirtiness, unhygienic conditions at kitchen shed in rural areas, to the extent of insects and lizards being spotted in food.
4. Fake enrolments are also done to embezzle money.

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone

J- निरोधात्मक एवं उपचारात्मक स्वास्थ्य क्या है।

निरोधात्मक

निरोधात्मक अर्थात् व्यक्ति को रोगी होने से बचने के लिए किये गये उपाय जिससे व्यक्ति को किसी भी प्रकार की बीमारी न हो।

इसमें हम निम्न कार्य भी लिखेंगे जैसे– संक्रामक रोगों का उन्मूलन, संगरोधन, जागरूकता, बेहतर पोषण आदि।

उपचारात्मक

उपचारात्मक स्वास्थ्य का अर्थ रोगग्रस्त होने के पश्चात व्यक्ति को पहुँचायें जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं से है।

इसके अन्तर्गत हम उपचारात्मक स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं सेवाओं का उल्लेख करेंगे। जैसे– आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम आदि।

निष्कर्ष में हम यह बायेंगे कि स्वास्थ्य केवल व्यक्तियों व परिवार के लिए नहीं वरन् किसी राष्ट्र की प्रगति, समृद्धि से जुड़ा हुआ है।

K- ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की स्थिति पर प्रकाश डालिये।

इस उत्तर में भूमिका में हम ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं का महत्व बतायेंगे।

इसके बाद हम ग्रमीण क्षेत्र में स्वास्थ्य की स्थिति जैसे– प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उपस्वास्थ्य केन्द्र, डॉक्टर पैरामेडिकल स्टॉफ की उपलब्धता, विभिन्न प्रकार बिमारियों की स्थिति आदि का आकड़ों सहित वर्णन करेंगे।

इसके पश्चचात ग्रामीण क्षेत्र सरकार के कुछ प्रमुख स्वास्थ्य कार्यक्रम लिखेंगे एवं बेहतर स्थिति के लिए सुझाव देंगे।

5. Reports have also shown children falling ill and being hospitalised due to poor quality of Mid-day mill.

J. What is Preventive and Curative Health?

Preventive Health:- Preventive care refers to prevention of occurrence of a disease or prevention of the complications if the disease has already occurred. For e.g blood pressure, depression, cholesterol etc. Broadly, it is of 5 types:

- Primordial prevention
- Primary prevention
- Secondary prevention
- Tertiary prevention
- Quaternary prevention

Curative Health :-Curative care implies to treatment of a medical pathology such that the patient becomes free from the disease/pathology process along with its symptoms. For example: Antibiotics in bacterial infection, surgery of an excisable tumor or the chemotherapy for other treatable diseases.

K. Highlight the Condition of Health Services in Rural India.

Rural Health Care services in India is mainly based on Primary health care, which envisages attainment of healthy status for all. Also being holistic in nature it aims to provide preventive, promote curative and rehabilitative care services. The different Health Policies and Programmes of the country aim at achieving an acceptable standard of health for the general population of the country. Keeping in line with this broad objective, a comprehensive approach was advocated, which included improvements in individual health care, public health, sanitation, clean drinking water, access to food and knowledge of hygiene and feeding practices. Importance was accorded to reduce disparities in health across regions and communities by ensuring access to affordable health, especially to the weaker and underprivileged like women and children, the older persons, disabled and tribal groups. An assessment of the performance of the country s health related indicators depicts that significant gains have been made in them e.g. life expectancy at birth, child and maternal mortality, morbidity.

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone

L- म.प्र. लोकसेवा आयोग की भर्ती प्रणाली को समझाइये।

इसके उत्तर में हम पहले मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के संविधानिक प्रावधान बतायेंगे।

उसके बाद भर्ती के निम्न तरीके बतायेंगे।

1. प्रत्यक्ष भर्ती
2. पदोन्नति
3. प्रतिनियुक्ति

इसके बाद हम उपरोक्त तरीकों की व्याख्या करेंगे।अन्त में भर्ती प्रणाली की उपयोगिता लिखें।

L. Throw light on the recruitment system adopted by the Madhya Pradesh Public Service Commission.

State Public Service Commissions must be consulted in all matters of recruitment except for the posts specified in the Constitution of India under Article 320, clause (4) of Article 16, Article 335 and 336 to be read along with State Public Service Commission (Limitation of Functions) Regulations.

Recruitment to the State Services is made through :-

I. Direct Selection
II. Promotions
III. Transfer of services on deputation from one department to another or from one State Government to another.

MPPSC conducts examination for various posts .Generally the pattern contains a preliminary exam ,mains and usually a interview.The most important exam conducted by MPPSC is the State Adminstrative Examination .

A. Write a short essay on the Information Technology Act, 2000. Can this act be misused by the Government?

Introduction :- The Information Technology Act, 2000 was notified on October 17, 2000. It

www.kautilyaacademy.com

www.facebook.com/KTSZone

KAUTILYA ACADEMY INDORE

PART- B 15 Marks

A- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम,2000 पर लघु निबंध क्या इस अधिनियम का सरकार द्वारा गलत उपयोग हो सकता?

– सूचना तकनीक अधिनियम (Information Technology Act 2000) भारतीय संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जो 17 अक्टूबर 2000 को पारित हुआ। 27 अक्टूबर 2009, को एक घोषणा द्वारा इसे संशोधित किया गया।

संयुक्त राष्ट्र संकल्प के बाद भारत ने मई 2000 में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 पारित कर दिया और 17 अक्टूबर 2000 को अधिसूचना जारी कर इसे लागू कर दिया। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 को सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम, 2008 के माध्यम से काफी संशोधित किया गया है, जिसे 23 दिसम्बर को भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था।

<u>उद्देश्य</u>– सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 निम्नलिखित मुद्दों को को संबोधित करता है–

– इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को कानूनी मान्यता
– डिजिटल हस्ताक्षर को कानूनी मान्यता
– अपराध और उल्लंघन
– साइबर अपराधों के लिए न्याय व्यवस्था। आदि।

सरकार इस एक्ट का दुरूपयोग निम्न तरीके से कर सकती है।

1. इंटरनेट बंद करना।
2. लोगों के संदेश एवं सोशल मीडिया पर अपनी नजर रखना।
3. किसी वेबसाइट, किसी एप को प्रतिबंधित करना।
4. सोशल मीडिया के तहत् भेजे गये संदेशों के आधार पर किसी पर न्यायिक कार्यवाही करना। आदि।

अन्त करते समय हम यह भी लिखेंगे कि सरकार का उद्देश्य धारा 69 A के तहत इसक उद्देश्य एकता अखण्डता स्थापित करना, सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखना। विभिन्न देशों के बीच मैत्री संबंधों को बनाये रखना है।

B. WHO की संरचना एवं कार्य एवं उद्देश्य–

विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization] WHO) विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं मानक विकसित

is the law that deals with cybercrime and electronic commerce in India.

India became the 12th country to enable cyber law after it passed the Information Technology Act, 2000.

Objectives of the Act:-

1. Grant legal recognition to all transactions done via electronic exchange of data or other electronic means of communication or e-commerce.
2. Give legal recognition to digital signatures for the authentication of any information or matters requiring legal authentication.
3. Facilitate the electronic filing of documents with Government agencies and also departments.
4. Facilitate the electronic storage of data.
5. Give legal sanction and also facilitate the electronic transfer of funds between banks and financial institutions.

Features of the Information Technology Act, 2000:-

1. All electronic contracts made through secure electronic channels are legally valid.
2. Legal recognition for digital signatures.
3. Security measures for electronic records and also digital signatures are in place.
4. A procedure for the appointment of adjudicating officers for holding inquiries under the Act is finalized.
5. Provision for establishing a Cyber Regulatory Appellant Tribunal under the Act.

Misuse by the government

- The government can use this act to stifle the free speech of citizens.

B. Describe the Structure, Functions and Objective of W.H.O.

Introduction:- The World Health Organisation (WHO) is the specialized organization for international health within the United Nation's system. WHO experts produce health guidelines and standards, and help countries to address public health issues. World Health Organisation also supports and promotes health research.

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone

करने की एक महत्त्वपूर्ण संस्था है। इस संस्था की स्थापना 7 अप्रैल, 1948 को की गयी थी। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक अनुषांगिक इकाई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के 193 सदस्य देश तथा दो संबद्ध सदस्य हैं। इसका उद्देश्य संसार के लोगों के स्वास्थ्य का स्तर ऊँचा करना है। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय स्विटजरलैंड के जेनेवा शहर में स्थित है। भारत भी विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक सदस्य देश है और इसका भारतीय मुख्यालय राजधानी दिल्ली में स्थित है।

संगठन के उद्देश्य–

1. मातृ नवजात, बाल एवं किशोर स्वास्थ्य।
2. संचारी रोग नियंत्रण।
3. असंचारी रोग एवं स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारक
4. सर्वोभोम स्वास्थ्य सेवा प्रसार।
5. सतत् विकास एवं स्वास्थ्य पर्यावरण।
6. स्वास्थ्य तंत्रो का विकास।
7. स्वास्थ्य सुरक्षा व आपात स्थितियाँ।
8. संसार के लोगों के स्वास्थ्य का स्तर ऊँचा करना। आदि।

संगठन के कार्य–

1. विश्व में स्वास्थ्य संबंधी मामलों में नेतृत्व प्रदान करना।
2. स्वास्थ्य अनुसंधान एजेण्डा का आकार देना।
3. नियत एवं मानक तय करना।
4. प्रमाण आधारित नीतिगत विकल्प पेश करना।
5. देशों को तकनीकी समर्थन प्रदान करने और स्वास्थ्य संबंधी रूझानों की निगरानी एवं आंलन करना। आदि।

C. भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का संक्षेप में वर्णन–

भारत सरकार की संचालित योजनाएं–

1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
2. जननी सुरक्षा योजना।

WHO came into formal existence in 1948 as the UN specialist agency for health, incorporating several existing organizations that represented a long history of international health cooperation.

Organization of WHO:- The World Health Assembly is the decision making body of World Health Organisation. It is attended by delegations from all World Health Organisation Member States and focuses on a specific health agenda prepared by the executive board.The main functions of the World Health Assembly are to determine the policies of the Organization, appoint the Director-general , supervise financial policies and ,review and approve the proposed programme budget. The Health Assembly is held annually in Geneva, Switzerland.

The Executive board is composed of 34 technically qualified members elected for three year terms.

Main Functions and Objectives of W.H.O are:-

1. to act as the directing and co-ordinating authority on international health work.
2. to assist governments, upon request , in strengthening health services.
3. to furnish appropriate technical assistance and in emergencies necessary aid upon the request of Governments.
4. to stimulate and advance work to eradicate epidemic, endemic and other diseases.
5. to promote , in co-operation with other specialized agencies where necessary.
6. to promote and conduct research in the field of health.
7. to establish and revise as necessary international nomenclatures of diseases , of cause of death and of public health practices.

C. Briefly describe schemes run by the Government in the field of healthcare in India.

1. Reproductive, Maternal, Newborn, Child and Adolescent Health (RMNCH+A)
2. Rashtriya Bal Swasthya Karyakram (RBSK)
3. The Rashtriya Kishor Swasthya Karyakram
4. National AIDS Control Organisation
5. Revised National TB Control Programme
6. National Leprosy Eradication Programme
7. Mission Indradhanush

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone
KAUTILYA ACADEMY INDORE

3. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम
4. प्रधान मंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना
5. राष्ट्रीय आयुष मिशन
6. राष्ट्रीय फ्लोरीसिस रोकथाम एवं नियंत्रण
7. राष्ट्रीय रक्त नीति
8. मिशन इन्द्रधनुष
9. राष्ट्रीय मुख स्वास्थ्य कार्यक्रम
10. राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम। आदि।

D. सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा की स्थिति को सुधारने के लिए किए गए कार्य–

भूमिका में प्राथमिक शिक्षा के महत्व को बतायेंगे। फिर हम कार्यों को निम्नानुसार लिखेंगे।

86 वां संविधान संसोधन, शिक्षा का अधिकार, राष्ट्रीय उपलब्धी सर्वेक्षण, ग्रेडिंग सिस्टम, ई लर्निंग, ई–पाठशाला, National Digital Library , SWAYAM, आदि।

1. पढ़े भारत बढ़े भारत।
2. मध्याह्न भोजन योजना(मिड डे मील)
3. महिला समाख्या कार्यक्रम।
4. सर्व शिक्षा अभियान।
5. बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीईजीईएल)
6. शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम
7. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय
8. अल्पसंख्यक संस्थानों में आधारभूत संरचना विकास योजना (आईडीएमआई)
9. शिक्षा गारंटी योजना।
10. जिला शिक्षा प्राथमिक कार्यक्रम।
11. मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा चलाये गये कार्यक्रमों का भी जिक्र करेंगें। आदि।

इसके अलावा हाल ही में कस्तुरीरंगनन समिति का भी जिक्र करेंगे।

अन्त में निष्कर्ष प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में की गई उपलब्धियों को आकड़ों के साथ 20 से 30 शब्दों में लिखें।

8. Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana (PMSSY)
9. Integrated Child Development Service
10. Rashtriya Swasthya Bima Yojana
11. National Tobacco Control Programme
12. Pulse Polio

(Explain Points)

D. Write a note on efforts made by the government for improving the state of Elementary education in India.

- **SWAYAM** MOOCs portal ((Study Webs of Active learning for Young Aspiring Minds) is an indigenous MOOCs portal that provides high quality education - anyone, anytime, anywhere at no cost- has been made operational
- To reach high quality educational content to the most backward areas using satellite communication, 32 DTH channels have been made functional, under **SWAYAM Prabha** programme
- The initiative of **National Digital Library (NDL)** is a virtual repository of learning resources with a single window search facility.
- **Unnat Bharat Abhiyan (UBA)** is a new initiative to make use the knowledge base in the higher educational institutions for plugging technology gaps in the rural areas.
- Recently, the Government has constituted a **Committee to draft National Education Policy** under the Chairmanship of eminent scientist Dr. K. Kasturirangan which is expected to submit its report soon
- **Uchchtar Avishkar Yojana (UAY)** has been launched to promote industry specific need-based research so as to keep up the competitiveness of Indian industry in the global market
- There is a provision made by the government for providing universal access, retention and quality in elementary education with a special emphasis on girls
- Sarva Shiksha Abhiyan is a significant step in providing elementary education to all children in the age group 6–14.
- There is also an establishment of schools like Navodaya Vidyalaya in each district to provide education to children
- Vocational streams have been developed to equip a large number of high school students with occupations related to knowledge and skills
- Bridge courses and back to school camps have been initiated to increase the enrolment in elementary education

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone